भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2653
बुधवार, 11 अगस्त, 2021/20 श्रावण, 1943 (शक)

देश में बेरोजगारी दर में वृद्धि

2653. डा. किरोड़ी लाल मीणाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में रोजगार/बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बेरोजगारी दर में तीव्र वृद्धि हुई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और बेरोजगारी पर रोक लगाने के संबंध में क्या प्रस्ताव है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)**,** सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से **2017-18** से एकत्र किए जा रहे हैं। वर्ष 2017-18, **2018-19** एवं **2019-20** के दौरान आयोजित किए गए पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार**,** देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) तथा अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) का उपलब्ध सीमा तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों सहित नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए तथा रोजगार की पुनःबहाली के लिए **1** अक्तूबर**,** 2020 से आरंभ की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि को **30** जून**, 2021** से बढ़ाकर **31** मार्च**, 2022** किया गया है।

पीएम स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को कोविड़ पश्च अवधि के दौरान फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए **10,000/-** रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने के कार्य को सरल बनाया है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए **10** लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए, सरकार देश में पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों तथा उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 11-08-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2653 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) दृष्टिकोण के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का उपलब्ध सीमा तक कामगार जनसंख्या अनुपात तथा बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

(प्रतिशत में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कामगार जनसंख्या अनुपात			बेरोजगारी दर		
	2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20
आंध्र प्रदेश	57.2	54.8	55.5	4.5	5.3	4.7
अरुणाचल प्रदेश	42.3	40.9	44.3	5.8	7.7	6.7
असम	43.7	43.4	43.2	7.9	6.7	7.9
बिहार	35.5	36.4	39.7	7.0	9.8	5.1
छत्तीसगढ	62.4	61.2	65.4	3.3	2.4	3.3
दिल्ली	42.7	44.5	43.3	9.4	10.4	8.6
गोवा	42.9	45.9	47.3	13.9	8.7	8.1
गुजरात	47.4	49.7	54.7	4.8	3.2	2.0
हरियाणा	41.7	41.9	42.9	8.4	9.3	6.4
हिमाचल प्रदेश	58.9	63.9	70.5	5.5	5.1	3.7
जम्मू और कश्मीर	51.0	52.9	52.5	5.4	5.1	6.7
झारखंड	41.7	44.9	53.6	7.5	5.2	4.2
कर्नाटक	49.1	49.3	53.1	4.8	3.6	4.2
केरल	41.2	44.9	45.3	11.4	9.0	10.0
मध्य प्रदेश	54.3	52.3	57.7	4.3	3.5	3.0
महाराष्ट्र	50.5	50.6	55.7	4.8	5.0	3.2
मणिपुर	42.5	44.3	45.5	11.5	9.4	9.5
मेघालय	62.3	61.8	58.6	1.6	2.7	2.7
मिजोरम	46.4	45.6	50.7	10.1	7.0	5.7
नागालैंड	32.8	38.1	44.8	21.4	17.4	25.7
उड़ीसा	44.9	47.6	51.9	7.1	7.0	6.2
पंजाब	42.9	44.2	47.8	7.7	7.4	7.3
राजस्थान	48.2	50.0	55.0	5.0	5.7	4.5
सिक्किम	58.7	61.1	68.8	3.5	3.1	2.2
तमिलनाडु	51.0	51.4	55.3	7.5	6.6	5.3
तेलंगाना	49.8	50.6	55.7	7.6	8.3	7.0
त्रिपुरा	42.0	41.9	49.6	6.8	10.0	3.2
उत्तराखंड	40.6	41.4	49.5	7.6	8.9	7.1
उत्तर प्रदेश	41.8	40.8	45.1	6.2	5.7	4.4
पश्चिम बंगाल	47.8	49.7	49.7	4.6	3.8	4.6
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	48.7	49.1	49.8	15./8	13.5	12.6
चंडीगढ़	46.9	47.3	45.5	9.0	7.3	6.3
दादर और नगर हवेली	66.3	68.6	72.2	0.4	1.5	3.0
दमन और दीव	63.2	55.1	64.5	3.1	0.0	2.9
लक्षद्वीप	34.4	29.5	48.0	21.3	31.6	13.7
पुडुचेरी	37.8	47.8	47.7	10.3	8.3	7.6
लद्दाख	-	-	62.7	-	-	0.1
अखिल भारत	**46.8**	**47.3**	**50.9**	**6.0**	**5.8**	**4.8**

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।